जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 18 संख्याः 48 प्रभात जालोर, शुक्रवार 26 मई, 2023 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

हाल ही में प्रकाशित एक शोध के अनुसार इण्डोनेशिया के जावा द्वीप में जावन लैपर्ड का आवास वर्ष 2000 से 2020 के बीच 1300 वर्ग किलोमीटर से अधिक घट गया है। शोधकर्ताओं ने लैपर्ड्स की उपस्थिति पर असर डाल सकने वाले कई कारकों को देखा, जैसे प्राइमरी और सैकण्डरी वनों का फैलाव, प्लान्टेशन्स, नदी और इंसानी बस्ती से दूरी आदि। वैज्ञानिकों ने पूर्व के मॉनिटरिंग डेटा का अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि 12,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जावन लैपर्ड के प्राकृतिक आवास के लिए अनुकूल होगा, जो कि जावा की कुल धरती का 10 वां भाग है। शोध में पता चला कि, वर्ष 2000 में लगभग 2481 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लैपर्ड के एकदम अनुकूल माना गया था, पर 2020 तक यह क्षेत्र 40 प्रतिशत घटकर मात्र 1430 वर्ग किलोमीटर ही रह गया। जावन लैपर्ड इस द्वीप के जीवित बचे एक मात्र बड़े परभक्षी हैं, परंतु अवैध शिकार, भोजन की कमी, आवास विनाश व जंगल के विघटन से इनकी संख्या कम हो रही है। एक अनुमान है कि, गंभीर रुप से संकटग्रस्त इस प्रजाति के केवल 350 सदस्य ही रह गए हैं और ये भी जंगल के ऐसे खंडों में रहते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इण्डोनेशिया के एक एन.जी.ओ. ''सिन्टास'' के डायरैक्टर हारियो ''वीबक'' वीबीसोनो ने इन नतीजों का स्वागत करते हुए कहा, यह शोध पत्र बताता है कि, जावन लैपर्ड जंगल की दुर्दशा और अलग-थलग विघटित आवासों व आबादी के कारण संकटग्रस्त स्थिति में आए हैं। आज जावन लैपर्ड की स्थिति, जितनी सोची थी, उससे भी ज्यादा कठिन है। सिन्टास और जावन लैपर्ड फोकस नाम की संस्था के संस्थापक अर्विन विलिआंतो ने कहा कि, शोध पत्र बताता है कि लैपर्ड के आवास में कोई कनैक्टिविटी नहीं है और इनका आवास निरंतर सिकुड़ रहा है। विलिआंतो ने कहा कि, उपयुक्त (सूटेबल) आवास का अनुमान लगाना इस प्रजाति की इकॉलजी के लिए आवश्यक है।

कर्नाटक में मंत्रिमण्डल के गठन पर चल रहे मंथन के कारण दिल्ली की मीटिंग स्थगित

यह बैठक खड़गे ने आहूत की है, तथा राहुल गांधी भी भाग लेंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- बैठक में पायलट का आना भी निश्चित सा है, क्योंकि पायलट के खेमे व पायलट की शिकायत मु.मंत्री गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व प्रभारी रंधावा से है, खड़गे व राहुल से नहीं।
- हाईकमान पूर्णतया प्रयासरत है कि, राजस्थान में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित हो, चुनाव के पहले। क्योंकि, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति ठीक है, पर, यह भी साफ जाहिर है कि, गहलोत व पायलट में झगड़ा बरकरार रहा तो, चुनाव में परिणाम काफी बिगड़े हुए आने की प्रबल संभावना बनती है।
- बैठक में काफी ''फ्री'' व ''फ्रैंक'' बातचीत होने की चर्चा है। क्योंकि, जब तक दोनों के गुबार नहीं निकलते, कांग्रेस की सरकार ''रिपीट'' होने की संभावना नहीं लगती।
- पर, क्या मौके का फायदा उठाकर गहलोत यह समझा पायेंगे कि, किन मजबूरियों के कारण वे पूर्व मु.मंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाये थे।

नई दिल्ली, 25 मई। तमाम अटकलों व संदेहों को दरकिनार करते हुए यह माना जा रहा है कि दिल्ली में राजस्थान के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाए जाने के लिए बुलाई गई बैठक में सचिन पायलट भी शामिल होंगे। राजस्थान में इस वर्ष के अंत तक चुनाव होंगे।

मीटिंग 26 मई को शाम 4 बजे होने वाली थी पर अब इसे आगे खिसका दिया गया है क्योंकि कर्नाटक में मंत्रिमण्डल विस्तार पर अभी फैसला नहीं हुआ है। विधानसभा चुनावों की रणनीति से सम्बन्धित बैठक कर्नाटक का मसला हल होने के बाद ही होगी। राजस्थान की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। इसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे।

इस मीटिंग में अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि गहलोत किसी भी कीमत पर गहलोत के साथ सन्त में भागीदारी करना नहीं चाहते है।

सूत्रों का कहना है कि मीटिंग खड़गे ने बुलाई है इसलिए कोई कारण नहीं है कि राहुल व पायलट इसमें शामिल ना हों क्योंकि समस्या तो मुख्य रूप से गहलोत, डोटासरा व रंधावा के साथ है।

डोटासरा व रंधावा तो गहलोत के एजेंट के रूप के काम कर रहे है।

मीटिंग में खुली एवं निष्पक्ष चर्चा होने की संभावना है जिसमें नेता कांग्रेस के दूसरी बार सत्ता में आने का राह में आने वाली बाधाओं से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे उठा सकते हैं।

यद्यपि नेतृत्व जमीनी और वास्तविक मुद्दों से पूर्णतया वाकिफ है और पार्टी जीतने की सहज स्थिति में नहीं है, खासकर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की तुलना में जहां कांग्रेस काफी आगे है। देखने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार मामलों की जांच के मुद्दे पर बैठक में चर्चा होगी या नहीं और क्या गहलोत यह बता सकते है कि उन्होंने वसुंधरा के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया और उनके भ्रष्टाचार पर कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की।

'लोकसभाध्यक्ष से पत्रकारों पर लगी पाबंदी हटाने की मांग'

प्रैस क्लब ऑफ इण्डिया ने लोकसभाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि, इन पाबंदियों के कारण, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें प्रैस गैलरी का स्थायी पास भी मिला हुआ है, संसद में प्रवेश नहीं कर पा रहे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मई। प्रैस क्लब ऑफ इण्डिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से अपील की है कि वे मीडिया पर लगे उन प्रतिबंधों को हटा दें, जिनके चलते पत्रकारों को संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है।

- प्रैस क्लब ऑफ इण्डिया ने यह भी कहा कि, ये पाबंदियाँ, कोविड-19 के कारण लगायी गयी थीं, पर, अब पूरे देश में कोविड का प्रकोप काफी घट गया है, तथा लगभग सभी राज्यों ने कोविड की वजह से लगायी गयी पाबंदियाँ हटा दी हैं। अतः लोकसभा को भी अब पत्रकारों को संसद की कार्यवाही कवर करने की पूरी सुविधा व आज़ादी दे देनी चाहिये।
- कई सांसदों व राजनीतिक नेताओं ने पत्रकारों की इस मांग का पूरा समर्थन किया है।

क्लब-अध्यक्ष उमाकांत लखेरा तथा महासचिव विनय कुमार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचने की कोशिश की गई है कि पिछले कई सत्रों के दौरान संसद की कार्यवाही की कवरेज करने वाले पत्रकारों एवं संवाददाताओं के प्रवेश पर लगाये गये कठोर प्रतिबंध अभी भी जारी हैं, जबकि ये प्रतिबंध कोविड-19 के परिणामस्वरूप लगाये गये थे।

पत्र में कहा गया है कि जहाँ हमारे कुछ साथियों को संसद में पहुँचने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, वहीं पिछले कई दशकों से संसद की कार्यवाही को कवर करते आ रहे बहुत से पत्रकारों को ऐसा अवसर देने से अब भी इंकार किया जा रहा है, जबकि उनके पास प्रैस गैलरी के स्थाई पास मौजूद हैं।

पत्र में जोर देते हुये कहा गया है कि पिछले कई सत्रों के दौरान स्थिति के धीरे-धीरे सहज होने के साथ ही हमने विभिन्न अवसरों पर इस मुद्दे को बार-बार उठाया है तथा इन अनावश्यक प्रतिबंधों, जिनका कोई तार्किक आधार या औचित्य नहीं है, की ओर आपका भी ध्यान आकर्षित किया है।

पत्र में यहाँ तक कह दिया गया है कि चूँकि संसद में पत्रकारों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के पीछे कोई ठोस कारण या तर्क नहीं हैं, इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रतिबंध उस व्यापक एजेंडा का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य मीडिया पर नियंत्रण करना तथा प्रैस की स्वतत्रता को प्रतिबंधित कर देना है ताकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता तक स्वतंत्र समाचारों तथा जानकारियों के मुक्त प्रवाह को रोका जा सके।

यह माँग करते हुये कि निष्क्रिय हो चुकी (डिस्फंक्शनल) लोकसभा प्रैस एडवाइज़री कमेटी तत्काल पुनर्गठित की जाये, प्रैस क्लब अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन्स के नाम पर मीडिया से छुटकारा पाने की निरन्तर कोशिश की जा रही है, जबकि इस प्रकार के प्रतिबंध इस समय देश मे या दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों, समूहों या भीड़ में कहीं भी अस्तित्व में नहीं हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

2021 से जबर्दस्ती ''फोर्टिफाइड'' चावल खिला रही है सरकार

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मई। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह 2021 से लोगों को फोर्टिफाइड चावल खाने को मजबूर कर रही है

- कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि, उनकी सरकार ने बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के मान लिया कि, फोर्टिफाइड राइस फायदेमंद है और इसका वितरण शुरु कर दिया।

जबकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये चावल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं या हानिकारक।

कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह घोषणा की थी तब से सरकारी एजेंसियों ने इस चावल का वितरण शुरू कर दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कर्नाटक में सैक्युलर, पर मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिन्दुत्व!'

कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का सोच दिखाया, पर, मध्य प्रदेश में पार्टी के मु.मंत्री पद के उम्मीदवार, कमलनाथ हिन्दुत्व से पूर्णतया सहानुभूति दिखा रहे हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- वे माथे पर तिलक लगा कर, कई सार्वजनिक आयोजनों में नज़र आते हैं।
- कांग्रेस जिलों में आंदोलन कर रही है, पुजारियों को मंदिरों की ज़मीन के स्वामित्व का अधिकार देने के लिये।
- कांग्रेस ने भोपाल में एक ''धर्म संसद'' का भी आयोजन किया, जिसमें लगभग 1600 पुजारियों ने भाग लिया था।
- भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ''धर्म यात्रा'' भी आयोजित करने की सोच रही है। यात्रा के बाद, गांव स्तर पर, ''धर्म चौपाल'' भी आयोजित होगी।

नई दिल्ली, 25 मई। कांग्रेस ने भले ही कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा बहुत कुशलता से उठाया हो पर मध्यप्रदेश, जहां इस वर्ष के अंत तक चुनाव होने हैं, में पार्टी ''सॉफ्ट हिंदुत्व'' (नर्म हिन्दुत्व) पर चलेगी। कांग्रेस राज्य के विभिन्न जिलों में रैलियां कर रही है और कलैक्टरों को ज्ञापन दे रही है कि मंदिरों की जमीन पर पुजारियों को पूर्ण अधिकार दिया जाए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी कमलनाथ वॉटस एप पर प्रचलित संदेशों और पोस्टर्स में माथे पर सिंदूर का टीका लगाए हुए दिख रहे हैं। इस वर्ष के पूर्व में पार्टी ने भोपाल में धर्म संसद भी आयोजित की थी जिसमें 1000 पुजारियों ने भी भाग लिया था। पार्टी की योजना है कि राज्य में भारत जोड़ो यात्रा की तरह धर्म यात्रा करवाई जाए इसके साथ ही हर गांव में ''धर्म चौपाल'' भी होगी और यह सब होगा नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले।

हरियाणा और पंजाब के डेरों की तरह मध्यप्रदेश में विभिन्न राजनैतिक दल कथावाचकों, संतों व पुजारियों का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश संत और कर्थावाचक जिनमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हैं, भाजपा समर्थक माने जाते हैं। पर कांग्रेस ने भी अपने समर्थक पुजारियों का एक समूह तैयार कर लिया है। ये वे हैं जो कई दशकों से मंदिर की जमीन पर स्वामित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुजारियों का समर्थन जीतने के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रवीण सूद सी.बी.आई. के नए डायरैक्टर

नई दिल्ली, 25 मई। भारतीय पुलिस (भा.पु.) सेवा के 1986 बैच (कर्नाटक संवर्ग) के अधिकारी प्रवीण सूद ने आज सी.बी.आई. के निदेशक का पदभार संभाला। सी.बी.आई. से जुड़ने के पहले, वे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यरत थे।

- कर्नाटक कैडर के प्रवीण सूद 1986 बैच के आई.पी.एस. अफसर हैं और 37 साल अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं।

सूद ने भा.पु. सेवा में अपने लगभग 37 वर्षों के लंबे कार्यकाल के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इनमें बेल्लारी व रायचूर के पुलिस अधीक्षक; अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) बेंगलुरु शहर; पुलिस आयुक्त, मैसूर शहर एवं बेंगलुरु शहर;

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पासपोर्ट के झमेले में फंस सकती है

अगर दिल्ली का कोर्ट राहुल गांधी को ''साधारण पासपोर्ट'' लेने के लिये, ''नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट'' देने से इंकार कर देता है, तो राहुल की अमेरिका यात्रा गफलत में फंस सकती है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दे रखी है कि, राहुल गांधी को नया पासपोर्ट जारी नहीं होना चाहिये।
- जैसा कि, विदित ही है, राहुल की संसद की सदस्यता, न्यायालय के आदेश से रद्द हो जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना ''डिप्लोमैटिक पासपोर्ट'' सरैण्डर कर दिया था।
- अभी तक तो न्यायालय का सोच है कि, यात्रा करने की स्वतंत्रता एक ''फण्डमैंटल अधिकार'' है किसी भी नागरिक का, और, राहुल कई बार विदेश यात्रा पर गये हैं, तथा उन्हें कभी न्यायालय से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है।
- पर, राहुल गांधी नैशनल हैरल्ड केस में आरोपित हैं, तथा दिसम्बर, 2005, को उन्हें इस मुकदमें में जमानत मिली हुई है, और जमानत देते समय कोई शर्त नहीं लगायी गयी थी।
- पर, सुब्रमण्यम स्वामी नैशनल हैरल्ड केस में मुख्य शिकायती हैं, अतः न्यायालय स्वामी को, राहुल को पासपोर्ट नहीं जारी होने के लिये, उनका पक्ष सुनने का मौका देना चाहती है।
- राहुल अपनी छः दिवसीय अमेरिका की यात्रा में सैनफ्रांसिस्को, वॉशिंगटन व न्यूयॉर्क जाना चाह रहे हैं, जहाँ वे प्रवासी भारतीय प्रेस को संबोधित करने का इरादा रखते है।

नई दिल्ली, 25 मई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी 30 मई को अमेरिका में तीन शहरों की 6 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, इस दौरान वे एन.आर.आई. समुदायों, बिज़नैस लीडर्स और मीडिया से वार्ता करेंगे, पर उनकी यात्रा कैंसिल हो सकती है, अगर दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें साधारण पासपोर्ट के लिए एन.ओ.सी. देने से इंकार कर दिया तो, राहुल द्वारा सामान्य पासपोर्ट मांगे जाने के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने मंगलवार को दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर कर और सामान्य पासपोर्ट के लिए एन.ओ.सी. मांगी। क्योंकि उन्होंने मार्च में संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। ज्ञातव्य है कि मानहानि के एक मुकदमे में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था। राहुल की याचिका सुनते हुए एडिशनल चीफ मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा कि, ट्रैवल करना मूल अधिकार है और अदालतों ने उनके विदेश जाने पर कभी भी रोक-टोक नहीं लगाई, वे पहले भी बिना अनुमति के कई बार विदेश जा चुके हैं।

इसी के साथ मेहता ने यह भी कहा कि पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को पूरा अधिकार है कि वे कांग्रेस नेता के प्रार्थना पत्र पर अपनी राय दे। राहुल गांधी नैशनल हैरल्ड केस में अभियुक्त हैं। इस केस में स्वामी शिकायतकर्ता हैं। कोर्ट ने स्वामी को शुक्रवार तक जवाब देने का कहा है। मजिस्ट्रेट मेहता ने कहा कि दिसम्बर 2015 को इस केस में राहुल को जमानत देते समय उनकी यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली स्वामी की याचिका खारिज कर दी थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नई संसद के उद्घाटन में 16 पार्टियां शामिल होंगी'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मई। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि सभी पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार नहीं कर रही हैं।

- भाजपा ने यह घोषणा करते हुए उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने वाली 16 पार्टियों की लिस्ट जारी की और कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे विपक्षी दलों को जवाब दिया।

भाजपा ने बताया कि 19 पार्टियां रविवार को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हैं, लेकिन 16 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पर सहमति जताई है।

जिन पार्टियों ने अपनी सहमति दी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)